भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2494
(जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947(शक) को दिया गया)

कॉर्पोरेट कर में कमी का प्रभाव

2494. **श्री शशांक मणिः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉर्पोरेट कर दरों में कमी के बाद कर संग्रह में समग्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो कर राजस्व वृद्धि के आंकड़ों सहित वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एप्पल और गूगल जैसी अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने हेतु विशिष्ट प्रोत्साहनों पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन पहलों से कर राजस्व और आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जी हाँ। निर्धारण वर्ष 2020-21 (कोविड प्रभावित वर्ष 2020-21 को छोड़कर) से कॉर्पोरेट कर की दरों में कमी के बाद प्रत्यक्ष कर संग्रह में समग्र वृद्धि हुई है। पिछले पाँच वर्षों में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
2019-20	10,50,681	-7.65%
2020-21	9,47,176 #	-9.85%
2021-22	14,12,422	49.12%
2022-23	16,63,686	17.79%
2023-24	19,60,166	17.82%
2024-25	22,26,375*	13.58%

स्रोत: प्रधान सीसीए (सीबीडीटी)

#कोविड प्रभावित वर्ष

*अनंतिम

(ग) से (च): घरेलू कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी वातावरण बनाने, नए निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम में धारा 115बीएए और धारा 115बीएबी पेश की गई थी। धारा 115बीएबी का प्रभाव नई विनिर्माण कंपनियों की महत्वपूर्ण वृद्धि में परिलक्षित होता है जो निर्धारण वर्ष 2022-23 में 2,928 से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में 7,185 हो गई है ।

स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलों के परिणामस्वरूप धारा 80आईएसी के तहत कटौती का दावा करने वाले स्टार्ट-अप्स की संख्या निर्धारण वर्ष 2022-23 में 328 से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में 877 हो गई है। इसके अलावा नए कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में धारा 80जेजेएए के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की संख्या निर्धारण वर्ष 2022-23 में 2,838 से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में 3,644 हो गई है ।

वित्त विधेयक के माध्यम से आयकर अधिनियम में विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इन कदमों से रोजगार सृजन, कर राजस्व में वृद्धि और समग्र आर्थिक विकास हुआ है।

कंपनियों को दिए गए कर लाभों के कारण कुल राजस्व प्रभाव वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में क्रमशः 88,109.27 करोड़ रुपये और 98,999.57 करोड़ रुपये (अनुमानित) रहा (स्रोत: प्राप्ति बजट 2025-26)। उपरोक्त कर लाभों का प्रभाव कॉर्पोरेटों को प्रतिस्पर्धी बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने और इस प्रकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर है।

*****